उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 | अंक 24 | 16-31 दिसंबर 2024 | ₹ 20/-

संघ प्रमुख के बयान पर उर्दू अखबारों की प्रतिक्रिया

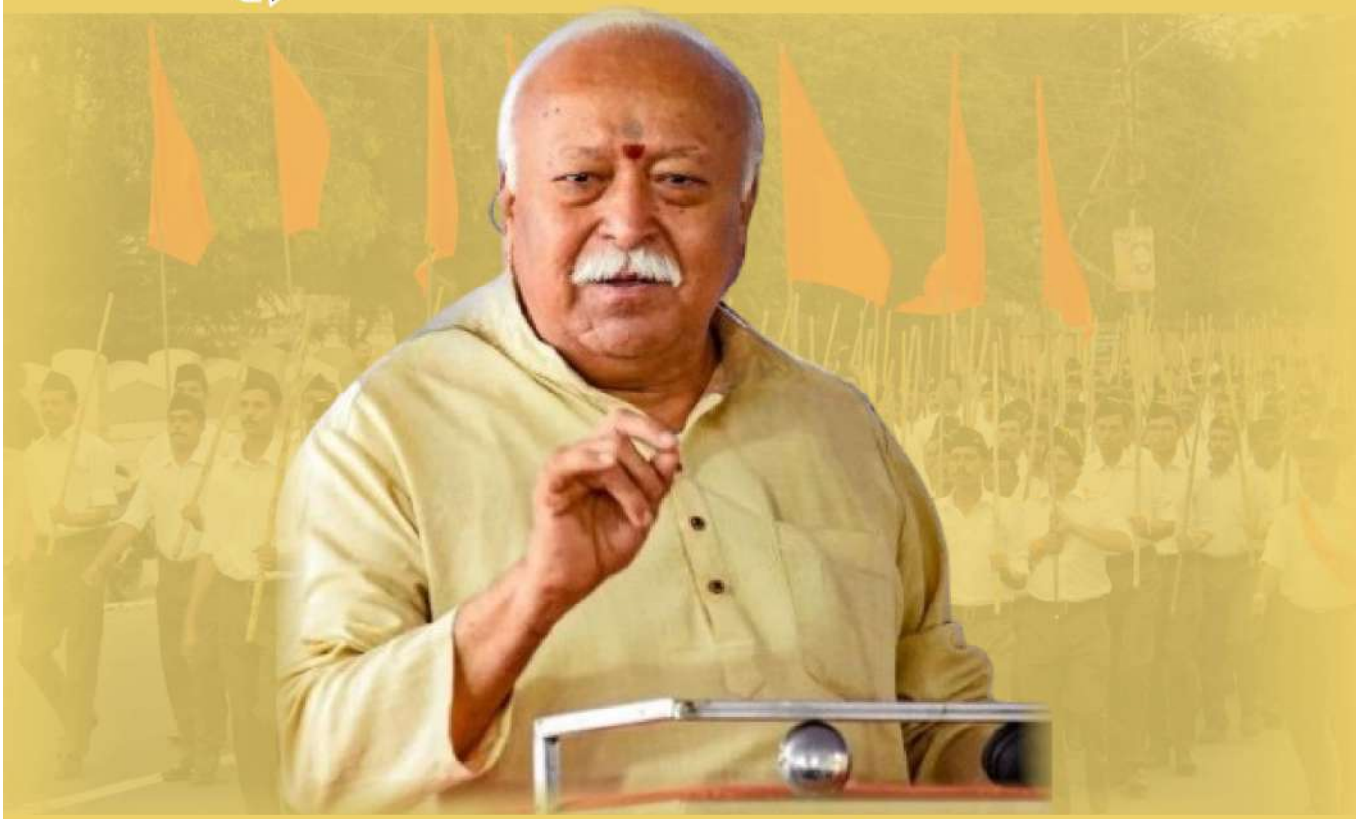

- प्रधानमंत्री मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान
- पाकिस्तानी हवाई हमलों में 50 से अधिक अफगानों की मौत
- सीरिया में शिया-सुन्नी गृहयुद्ध भड़का
- बांग्लादेश तब्लीगी इज्तिमा में दो गुटों के बीच खूनी झड़पें

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

संघ प्रमुख के बयान पर उर्दू अखबारों की प्रतिक्रिया 04
प्रधानमंत्री मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान 10
इस्लामिक वक्फ की हर कीमत पर रक्षा करने का संकल्प 13
चंदन गुप्ता हत्याकांड के 28 दोषियों को उम्रकैद 15
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणा 16

विश्व

पाकिस्तानी हवाई हमलों में 50 से अधिक अफगानों की मौत 17
बांग्लादेश तब्लीगी इज्तिमा में दो गुटों के बीच खूनी झड़पें 19
बांग्लादेश द्वारा भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग 22
अमेरिका और जर्मनी में इस्लामिक आतंकवादियों का कहर 25
अफगानिस्तान में अब खिड़कियों पर भी प्रतिबंध 27

पश्चिम एशिया

सीरिया में शिया-सुन्नी गृहयुद्ध भड़का 28
सीरिया में एक लाख से अधिक लोगों की हत्या का आरोप 32
सीरिया द्वारा ईरान से 300 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग 34
मिस्र में फिलिस्तीनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध 35
इजरायल द्वारा यमन पर भीषण बमबारी 35
तुर्किये की एक फैक्ट्री में विस्फोट 37

सारांश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने सुझाव दिया है कि मंदिर-मस्जिद के नए विवादों से बचा जाए ताकि देश में सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सद्भावना को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग मंदिर-मस्जिद पर विवाद खड़ा करके चर्चा में आना चाहते हैं और राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं। हिंदू हमेशा से सभी धर्मों का सम्मान करते आ रहे हैं। यही कारण है कि रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन में भी धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। मोहन भागवत के इस बयान का उर्दू मीडिया और मुस्लिम नेताओं ने मोटे तौर पर स्वागत किया है। उर्दू अखबारों ने कहा है कि अगर मोहन भागवत अपने इस बयान पर ईमानदार हैं तो उन्हें संघ परिवार से जुड़े संगठनों के नेताओं को भी यह निर्देश देना चाहिए कि वे मुसलमानों के खिलाफ नफरती अभियान पर लगाम लगाएं और हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग या मंदिर की तलाश करने के सिलसिले को बंद कर दें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कुवैत दौरा सफल रहा है। उन्हें कुवैत का सर्वोच्च सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर' से सम्मानित किया गया है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत में रहने वाले भारतीय लोगों को संबोधित करने के अतिरिक्त रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति से भी विशेष मुलाकात की है। उर्दू के प्रमुख अखबार **इंकलाब** ने नरेन्द्र मोदी के कुवैत दौरे पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हम भले ही मोदी की नीतियों से असहमति रखते हों, लेकिन हम यह स्वीकार करने पर मजबूर हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में अरब जगत के साथ भारत के संबंधों को नई उंचाइयों पर पहुंचाया है। समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि भारतीय मुसलमानों को मोदी से शिकायत हो सकती है, लेकिन अरब देशों के शासकों के लिए यह कोई मुद्दा नहीं है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों में दिन-प्रतिदिन तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान की सीमा का अतिक्रमण करते हुए अफगानिस्तान के कई गांवों पर बमबारी की थी। इस बमबारी में 50 से अधिक लोग मारे गए थे। जब अफगान सरकार ने इस पर विरोध प्रकट किया तो पाकिस्तान सरकार ने अपनी इस कार्रवाई को उचित ठहराते हुए यह तर्क दिया कि उसने यह हमला पाकिस्तान में उत्पात मचाने वाले इस्लामिक आतंकवादियों के ठिकानों पर किया है। अफगान सरकार ने पाकिस्तान के इस आरोप को निराधार बताया था। इसके बाद तालिबान सेना ने पाकिस्तान की चार सीमावर्ती चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस हमले में 20 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। विश्लेषकों की आशंका है कि दोनों देशों का यह सशस्त्र संघर्ष भविष्य में भीषण रूप धारण कर सकता है।

सीरिया में शिया-सुन्नी संप्रदाय के बीच फिर से गृहयुद्ध छिड़ गया है। गौरतलब है कि सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद शिया थे, इसलिए उन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त था। अब इस्लामिक आतंकवादी संगठन अलकायदा से संबंधित हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) नामक विद्रोही संगठन ने सीरिया की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इस संगठन का संबंध सुन्नी संप्रदाय से है। यही कारण है कि देश की नई सरकार ने शियाओं के पवित्र स्थलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अनेक विख्यात शिया दरगाहों को तबाह करके उनमें आग लगा दी गई है। इसके कारण एक बार फिर से शियाओं और सुन्नियों के बीच गृहयुद्ध की शुरुआत हो गई है। अब यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि भविष्य में सीरिया में एकता बरकरार नहीं रहेगी और इस देश के कई टुकड़े हो जाएंगे।

संघ प्रमुख के बयान पर उर्दू अखबारों की प्रतिक्रिया

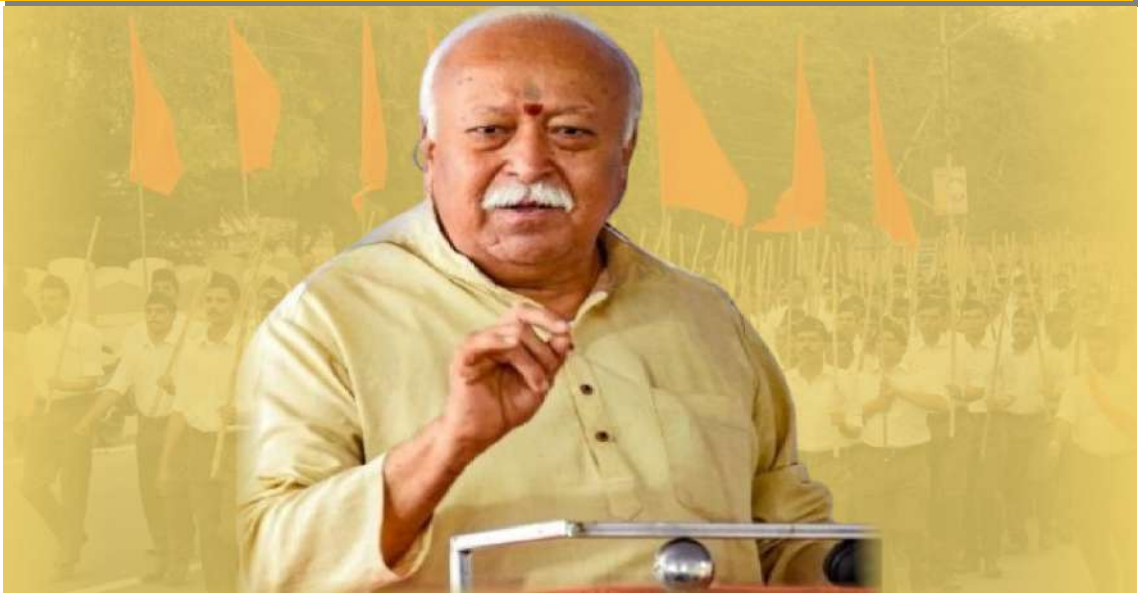

हाला ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने मंदिर-मस्जिद विवाद को समाप्त करने पर जोर दिया था। उर्दू मीडिया ने मोटे तौर पर उनके इस बयान का स्वागत किया है।

उर्दू टाइम्स (21 दिसंबर) के अनुसार पुणे में भाषण देते हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर-मस्जिद विवाद के दोबारा सिर उठाने पर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे इस तरह के मामले उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। मोहन भागवत पुणे मे आयोजित 'विश्वगुरु भारत' विषय पर अपने विचार रख रहे थे। उन्होंने बहु धर्म समाज का समर्थन करते हुए कहा कि दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि हम आपस में सद्भावना के साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है और ऐसा सिर्फ हिंदू ही कर सकते हैं। भागवत ने कहा कि बाहर से आने वाले कुछ गिरोह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वे यह चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आ जाए, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चल रहा है। इसी व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वे सरकार चलाते हैं। अब वर्चस्व के दिन खत्म हो चुके हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन कट्टरपंथी था। हालांकि, उनके ही वंश के बहादुर शाह जफर ने 1857 में गोवध पर प्रतिबंध लगा दिया था।

अखबार-ए-मशरिक (26 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मोहन भागवत का हालिया बयान भाईचारे और सामाजिक सद्भावना का संदेश देता है, लेकिन क्या वे अपने इस बयान पर ईमानदार हैं? या फिर यह आरएसएस और भाजपा की छवि को सुधारने की एक रणनीति है। समाचारपत्र ने कहा है कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के बाद देशभर में जो सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए थे उसके कारण मुसलमानों के दिलों में भय पैदा हुआ। इसके साथ ही देश की सेक्युलर नींव भी खतरे में पड़ गई। बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद,

मथुरा की शाही ईदगाह, अजमेर की दरगाह और अन्य मस्जिदों को लेकर खड़े किए गए विवादों ने मुसलमानों में असुरक्षा की भावना को फिर से पैदा कर दिया है। ऐसी स्थिति में मोहन भागवत का यह बयान अप्रत्याशित है, क्योंकि आरएसएस प्रारंभ से ही सांप्रदायिक विवादों को हवा देने के लिए मशहूर रहा है। गोरक्षा के नाम पर होने वाली लिंचिंग, लव जिहाद और घर वापसी जैसे नारों के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इन घटनाओं को देखते हुए यह सवाल पैदा होता है कि क्या भागवत का यह बयान एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता है या यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है?

सियासत (24 दिसंबर) के अनुसार जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने मोहन भागवत के बयान पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि मोहन भागवत केवल एक संगठन के निर्देशक हैं। वे हिंदू धर्म के निर्देशक नहीं हैं। मोहन भागवत का यह बयान उनके निजी विचार हैं और इससे तुष्टिकरण की भावना का संकेत मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण में संघ की कोई भूमिका नहीं है। जब संघ नहीं था तब भी हिंदू धर्म मौजूद था। संभल विवाद पर टिप्पणी करते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि अगर उन्होंने हमारे मंदिर गिराए हैं और वहां पर मस्जिद बनाई गई है तो क्या हमें अपने मंदिर को वापस लेने का अधिकार नहीं है? हम किसी को नहीं छेड़ते, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा।

उर्दू टाइम्स (24 दिसंबर) के अनुसार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मोहन भागवत के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि भूतकाल में विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धार्मिक स्थानों को ध्वस्त करके वहां पर मस्जिदें बना दी थीं। अगर हम उनकी वापसी की मांग करते हैं तो इसमें बुराई क्या है?

कौमी तंजीम (22 दिसंबर) के अनुसार कांग्रेस के नेता हुसैन दलवई ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि मोहन भागवत के कथनी और करनी में अंतर है। दलवई ने कहा कि संघ की ओर से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काई जा रही है। उनके घरों को बुलडोजरों से ध्वस्त किया जा रहा है और उनके धार्मिक स्थलों को हड़पने का अभियान चलाया जा रहा है। संघ की नीति प्रारंभ से ही मुस्लिम विरोधी रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहन भागवत इस तरह के बयान देकर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (24 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने उनसे मांग की है कि वे नित नए मंदिर-मस्जिद विवाद को उठाने वाले अपने अनुयायियों को भी यह निर्देश दें कि अब बहुत हो चुका। अब वे इसकी आड़ में हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश न करें। अजमेर दरगाह के सज्जादानशीन सैयद जैनुल आबेदीन अली खान और देश के मुस्लिम संगठनों ने मोहन भागवत के बयान पर सकारात्मक रूख अपनाया है। समाचारपत्र ने कहा है कि मोहन भागवत के इस बयान पर मुसलमानों को अधिक खुश होने की

जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक बयानबाजी है।

उर्दू टाइम्स (26 दिसंबर) ने कहा है कि मोहन भागवत इससे पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। इस पर मुसलमानों को सतर्क रहने की जरूरत है। एक ओर तो भागवत इस तरह के बयान दे रहे हैं। दूसरी ओर, उनके अनुयायियों ने संभल में जो हरकत की है वह रोंगटे खड़ी करने वाली है। अब तो इस तरह के विवाद की लपेट में मुसलमानों की कई महत्त्वपूर्ण मस्जिदें भी आ गई हैं।

मुंसिफ (25 दिसंबर) ने कहा है कि तथाकथित सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उनके इस बयान का असली लक्ष्य देश की सत्ता पर स्थाई कब्जा करना और आरएसएस के सांगठनिक ढांचे को मजबूत बनाना है ताकि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

कौमी तंजीम (31 दिसंबर) के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव डॉ. सुरेन्द्र जैन ने एक नया शोशा छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान काशी और मथुरा पर अपने दावे को छोड़ दें तो वे हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश करना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। मुसलमानों को हिंदुओं के उन पवित्र स्थलों को पुनः हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए जिन पर मुस्लिम शासनकाल में जबरन कब्जा किया गया था। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के मंदिर भी मुक्त होंगे। जैन ने कहा कि शांति प्रिय हिंदू समाज 1984 से काशी और मथुरा पर दावा कर रहा है। उस समय भी हमने मुसलमानों को यह प्रस्ताव दिया था कि वे इन दोनों स्थानों को हिंदुओं के हवाले कर दें तो हिंदू समाज अन्य स्थानों पर अपना दावा नहीं करेगा, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पहले अपना कट्टरपन छोड़ना होगा।

अखबार-ए-मशरिक (27 दिसंबर) ने मोहन भागवत के बयान की परोक्ष रूप से आलोचना की है। समाचारपत्र ने कहा है कि एक ओर तो मोहन भागवत सामाजिक सद्भावना का राग अलाप रहे हैं। दूसरी ओर, उनके अनुयायी संभल की शाही जामा मस्जिद सहित देश की दर्जनों मस्जिदों व दरगाहों पर अपना दावा कर रहे हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया है। इकरा हसन ने कहा है कि वह पहली बार मोहन भागवत के किसी बयान से सहमत हैं, लेकिन इसके साथ ही मोहन भागवत अपने अनुयायियों को भी यह निर्देश दें कि वे मुसलमानों की दरगाहों और मस्जिदों पर दावा करने के सिलसिले को बंद कर दें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर मोहन भागवत का यह बयान उनके दिल की आवाज है तो उन्हें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों के मुस्लिम विरोधी अभियान पर

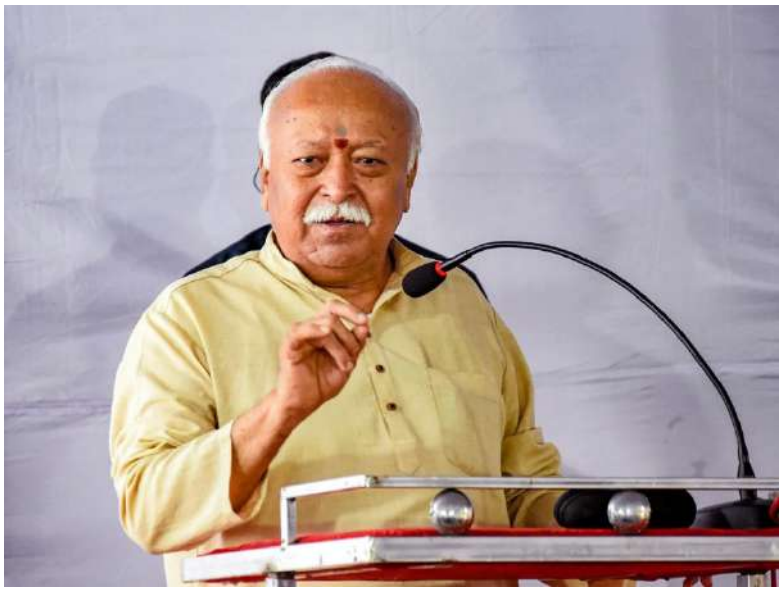

पाबंदी लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि मोहन भागवत अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश नहीं करते, जो इस देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में लगे हुए हैं।

हिंदुस्तान (29 दिसंबर) ने कहा है कि भागवत के इस बयान से पता चलता है कि उन्हें यह अनुभूति हो गई है कि कुछ सांप्रदायिक तत्व मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि मोहन भागवत के इन बयानों का असर उनके अनुयायियों पर रत्ती भर भी नहीं हो रहा है, बल्कि वे इसके उलट मस्जिदों और दरगाहों पर कब्जा जमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुकदमे कर रहे हैं। हम यह आशा करते हैं कि मोहन भागवत के इस बयान को देखते हुए सभी हिंदू पक्ष विभिन्न अदालतों में दायर अपने मुकदमे को वापस ले लेंगे। अगर मोहन भागवत ईमानदार हैं तो वे भाजपा के शासकों को भी अपनी इस नसीहत पर अमल करने का निर्देश दें। अगर ऐसा होता है तो वास्तव में हिंदुस्तान में राम राज्य स्थापित हो जाएगा।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (29 दिसंबर) ने अपने एक लेख में कहा है कि मुसलमानों को मोहन भागवत की चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। यह मुस्लिम दुश्मनी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी वे इस तरह के बयान देते आ रहे हैं, लेकिन उनके बयानों का असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। फासीवादी ताकतों ने मुसलमानों के खिलाफ अपना रवैया नहीं बदला है। मुल्क में जो फासीवाद बढ़ रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। संविधान और कानून की शपथ लेने वाले लोग मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और उन्हें हर तरह से परेशान किया जा रहा है।

उर्दू टाइम्स (23 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में मोहन भागवत को मशवरा दिया है कि वे पहले अपने कार्यकर्ताओं को राजधर्म का पालन करने का निर्देश दें। देश में जारी सांप्रदायिक राजनीति व मंदिर-मस्जिद विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चिंता ने सभी को हैरानी में डाल दिया है, क्योंकि ये विवाद आरएसएस के इशारे पर ही उठाए गए हैं और अब आरएसएस के प्रमुख ही इस पर चिंता प्रकट करने की नौटंकी कर रहे हैं। एक ओर तो मोहन भागवत मंदिर-मस्जिद विवाद पर चिंता प्रकट कर रहे हैं। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सांप्रदायिक बयानों से भागवत के बयान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसे देखते हुए हमारा मोहन भागवत को यह मशवरा है कि वे दूसरों को नसीहत देने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को ही काबू में कर लें तो पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा। जहां-जहां मुसलमानों के खिलाफ हिंसा

भड़काई जा रही है उनमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ही नाम सामने आते हैं। गांव-गांव में संघ की शाखाओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। इसे सिर्फ मोहन भागवत ही रोक सकते हैं।

अवधनामा (24 दिसंबर) ने कहा है कि मोहन भागवत की कथनी और करनी में भारी अंतर है। एक ओर तो वे इस तरह के सद्भावनापूर्ण बयान दे रहे हैं। दूसरी ओर, उनकी ही पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य में मुसलमानों के खिलाफ खुलकर अभियान चला रहे हैं। मुसलमानों की दरगाहों और मस्जिदों को हड़पने का प्रयास चल रहा है। अगर कोई सरकार की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे बंदूक की गोलियों से भून दिया जाता है और उसके मकानों को बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया जाता है।

हिंदुस्तान (20 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि एक ओर तो संघ प्रमुख मोहन भागवत सामाजिक सद्भावना का उपदेश दे रहे हैं। दूसरी ओर, देश में मुसलमानों का जीना दूभर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सदियों पुरानी मस्जिदों को मंदिरों में बदलने का अभियान चलाया जा रहा है। हर जिला हर कस्बे में ऐसी मस्जिद की तलाश की जा रही है, जिस पर मंदिर होने का दावा किया जा सके। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू से मकान खरीदता है तो उसके खिलाफ भी माहौल बनाया जाता है। दुख की बात यह है कि सांप्रदायिक तत्वों की नाजायज मांगों को दबाने के बजाय प्रशासन भी उन्हीं का साथ देता है।

हिंदुस्तान (22 दिसंबर) ने कहा है कि मोहन भागवत से लेकर नितिन गडकरी द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं उनका लक्ष्य विश्व को बेवकूफ बनाना और देश में मुसलमानों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर पर्दा डालना है। एक ओर तो मोहन भागवत सामाजिक सद्भावना का राग अलाप रहे हैं। दूसरी ओर, आरएसएस से जुड़े संगठन देश के भोले-भाले हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। दर्जनों मस्जिदों पर झूठे दावे करके देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की आड़ में भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की ज्वाला भड़काई जा रही है। देश के कई भागों में मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मोहन भागवत को बयान देने के बजाय इस मुस्लिम विरोधी अभियान को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हम यह समझते हैं कि जब तक मोहन भागवत इस संदर्भ में कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तब तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलेगा। मोहन भागवत न केवल अपने संगठनों को, बल्कि भाजपा की सरकार को भी कानून और संविधान के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी बातों का कोई मोल नहीं होगा।

हिंदुस्तान (31 दिसंबर) ने कहा है कि मोहन भागवत का संगठन उनके बयान पर कितना गंभीर है इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आरएसएस की अपनी पत्रिका 'ऑर्गेनाइजर' ने भी उनके इस बयान को मानने से इंकार कर दिया है।

रोजनामा सहारा (2 जनवरी) ने अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित समाचार में कहा है कि

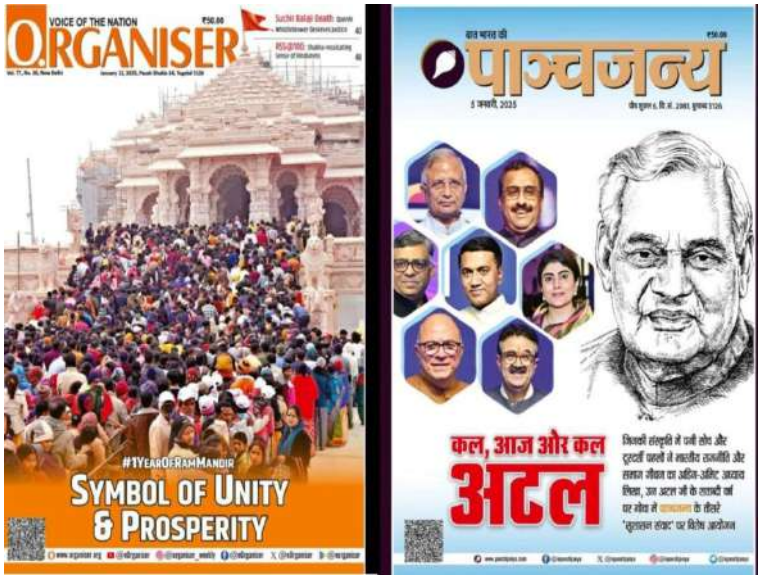

संघ के मुखपत्र 'पाञ्चजन्य' ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। पाञ्चजन्य के संपादक हितेश शंकर ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'मंदिरों पर यह कैसा दंगल!'। उन्होंने अपने संपादकीय में कहा है कि राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए मंदिरों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है और इसे राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। मोहन भागवत का इस संदर्भ में दिया गया बयान उनके गंभीर चिंतन और सामाजिक सरोकार का परिचायक है। पाञ्चजन्य ने कहा है कि भागवत के इस बयान के बाद मीडिया में लड़ाई जैसी स्थिति पैदा हो गई है। क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है? भागवत का यह बयान इस मामले को समझदारी से निपटाने का समाज से आग्रह है। ऐसे मामलों पर गैर-जरूरी बहस और दुष्प्रचार को प्रोत्साहन देना देश के लिए चिंताजनक है। कुछ समाज दुश्मन तत्व सोशल मीडिया पर लोगों की सामाजिक भावनाओं का शोषण कर रहे हैं। ऐसे तत्वों से दूर रहना जरूरी है। भारत एक ऐसी सभ्यता-संस्कृति का नाम है, जिसने सहस्रों वर्षों से विविधता में एकता के दर्शन को सिर्फ बताया ही नहीं, बल्कि इसे जिया और आत्मसात किया है। सरसंघचालक का यह बयान दर्शाता है कि हिंदू समाज को अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए राजनीतिक विवादों से दूर रहना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि मोहन भागवत ने 19 दिसंबर को पुणे में आयोजित एक समारोह मे कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को यह लगता है कि वे नए स्थानों पर ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हर रोज एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? देश को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं।

हालांकि, आरएसएस के एक अन्य मुखपत्र 'ऑर्गेनाइजर' ने अपने संपादकीय में मोहन भागवत के विचार से भिन्न मत प्रकट किया था। ऑर्गेनाइजर ने इसे ऐतिहासिक सच्चाई जानने और सांस्कृतिक न्याय का युद्ध बताया था। ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने अपने संपादकीय में लिखा था कि सोमनाथ से संभल तक और इससे आगे की ऐतिहासिक सच्चाई को जानने के इस प्रयास का धार्मिक वर्चस्ववाद से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अपने संपादकीय में कहा था कि कांग्रेस चुनावी लाभ के लिए जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को भड़का रही है। जबकि भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान में जातिवाद को दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास किया था। ■

प्रधानमंत्री मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान

कौमी तंजीम (23 दिसंबर) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुवैत दौरे के दौरान उन्हें कुवैत का सर्वोच्च सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर' से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने प्रदान किया। इस अवसर पर कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अल-अब्दुल्ला अल-अहमद अल-सबा भी मौजूद थे। पिछले 43 सालों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कुवैत का दौरा किया है। कुवैत सरकार ने इस सम्मान की घोषणा 1974 में की थी। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर कुवैत का एक नाइटहुड सम्मान है। इसे अब तक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल किल्टन, जॉज बुश और प्रिंस चार्ल्स जैसे विख्यात वैश्विक नेताओं को पेश किया जा चुका है। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी से संबंधित समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

सियासत (22 दिसंबर) के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने अब्दुल्ला अल-बैरन से भी मुलाकात की है। अल-बैरन ने रामायण और महाभारत का अनुवाद अरबी में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत के साथ भारत के संबंधों की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे संबंध शताब्दियों पुराने हैं। किसी समय कुवैत में भारतीय करेंसी भी चला करती थी। कुवैत में 10 लाख भारतीय रहते हैं, जो कुवैत की कुल जनसंख्या का 21 प्रतिशत है।

हिंदुस्तान (24 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुवैत दौरे का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इससे पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कुवैत का दौरा किया था। हालांकि, 2009 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी कुवैत का दौरा कर चुके हैं। कुवैत के अनेक प्रमुख लोगों ने भारत में इस्लाम विरोधी प्रवृत्ति और मुसलमानों के उत्पीड़न पर चिंता प्रकट करते हुए भारत के साथ कुवैत के संबंधों को समाप्त करने की भी मांग की थी। सत्तारूढ़ पार्टी की एक नेता ने जब पैगंबर-ए-इस्लाम के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो इस पर कुवैत सरकार ने भारत सरकार से विरोध प्रकट किया

था। भारत उन देशों में शामिल है, जिसने कुवैत की स्वायत्तता को सबसे पहले मान्यता दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत में कार्यरत 10 लाख भारतीयों की चर्चा करते हुए कहा कि यह वर्ग दोनों देशों के बीच पुल का काम कर रहा है।

समाचारपत्र ने कहा है कि कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को जो सर्वोच्च सम्मान दिया है वह दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए संबंधों का परिचायक है। मोदी के कुवैत दौरे से यह साफ है कि भारत की भाजपा सरकार को दुनिया के मुस्लिम देशों से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू बेहद अफसोसजनक है। देश के मुसलमान हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक तत्वों के निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे शरारती तत्वों पर लगाम लगानी चाहिए। तभी यह देश तरक्की कर सकता है। मोदी के कुवैत दौरे के दौरान एक दर्जन समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। मोटे तौर पर मोदी का यह दौरा न केवल सफल हैं, बल्कि इसके महत्त्वपूर्ण परिणाम भी निकले हैं। देश में शांतिपूर्ण वातावरण को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरती अभियान को फौरन बंद किया जाए, क्योंकि विदेशी पूंजी निवेश के लिए देश में शांतिपूर्ण वातावरण का होना बेहद जरूरी है।

अखबार-ए-मशरिक (24 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री मोदी के कुवैत दौरे का स्वागत किया है और कहा है कि जो लोग भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अभियान चला रहे हैं उन्हें यह सच्चाई क्यों नजर नहीं आती कि एक इस्लामिक देश ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। जबकि दूसरी ओर, हिंदुस्तान में मुसलमानों के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। एक ओर तो हिंदुस्तान में 'बंटोगे तो कटोगे', 'एक रहोगे तो सेफ रहोगे' के नारे लगाए जाते हैं। दूसरी ओर, आप यह आशा करते हैं कि अरब के मुस्लिम देशों से आपके संबंध मैत्रीपूर्ण रहेंगे।

सियासत (24 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कुवैत के शासकों के निमंत्रण के कारण संभव हुआ है। भारत और कुवैत के संबंध सदियों पुराने हैं। कुवैत से भारत को भारी मात्रा में पेट्रोल

प्राप्त होता है, जो देश की ऊर्जा के लिए महत्त्वपूर्ण है। भारत के विकास के लिए यह जरूरी है कि मध्य पूर्व के मुस्लिम देश भारत में ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश करें। इसके लिए इन देशों को यह विश्वास होना चाहिए कि भारत में मुसलमान शांतिपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं और उन्हें वहां पर किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

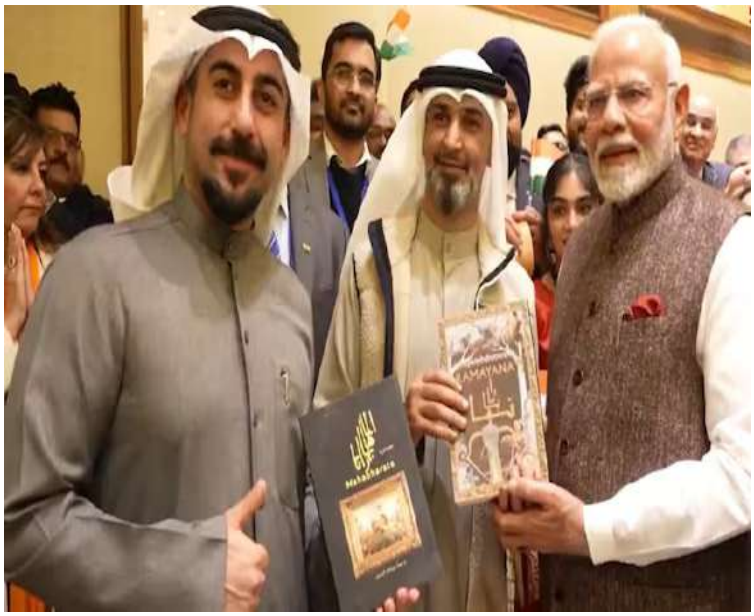

उर्दू टाइम्स (25 दिसंबर) ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का हालिया कुवैत दौरा मुस्लिम देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर तो भारत में मुसलमानों का जीना दूभर किया जा रहा है। दूसरी ओर, हम यह आशा करते हैं कि अरब देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री मोदी यह चाहते हैं कि वे भारत में मुसलमानों पर जुल्मो सितम करते रहें और मुस्लिम देश उनकी शान में यशोगान करते रहें ताकि वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री का कद बढ़ता रहे। समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार दुबई में जब एक मंदिर की आधारशिला रखी थी तो वहां की दो शहजादियों ने भगवद्गीता को अपने सिर पर रखकर उन्हें देवी-देवताओं की मूर्तियों के चरणों में पेश किया था। आज हमें खाड़ी देशों के अक्ल पर मातम करने का जी चाहता है। हिंदुओं को भारत की हर मस्जिद में मंदिर नजर आता है और वे उस मस्जिद को ध्वस्त करके वहां पर मंदिर बना देते हैं। अगर इसी रास्ते पर खाड़ी के मुस्लिम देश भी चलने लगें तो इसके क्या परिणाम होंगे इस पर हमारे शासकों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या हमारे शासक खाड़ी के मुस्लिम देशों में राम मंदिरों का निर्माण करके यह साबित करना चाहते हैं कि कभी ये देश भी राम और सीता के निवास स्थान रहे हैं? जिस दिन ऐसा हुआ वह दिन मुसलमानों और इस्लाम के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

इंकलाब (2 जनवरी) ने कहा है कि हम मोदी की नीतियों से असहमति रखते हैं, लेकिन हम यह स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को नई उंचाइयों तक पहुंचाया है। भारतीय मुसलमानों को मोदी से शिकायत हो सकती है, लेकिन अरब देशों के शासकों के लिए यह कोई समस्या नहीं है। आपको याद होगा कि जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 का खात्मा किया गया तो इसके खिलाफ पाकिस्तान ने इस्लामिक जगत में काफी बवाल मचाया था, लेकिन इसके बावजूद किसी भी अरब देश ने मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ चूं तक नहीं की। अंतरराष्ट्रीय संबंध धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविकता, तथ्यात्मकता और आपसी हितों को देखते हुए कायम किए जाते हैं। भारत जैसी बड़ी ताकत और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना मुस्लिम देशों के हित में है।

इस्लामिक वक्फ की हर कीमत पर रक्षा करने का संकल्प

औरंगाबाद टाइम्स (20 दिसंबर) के अनुसार हाल ही में लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अदालतों में दायर मस्जिदों के सर्वे से संबंधित याचिकाओं पर चिंता प्रकट की गई। बोर्ड ने एक प्रस्ताव के जरिए सरकार को यह चेतावनी दी है कि मुसलमान किसी भी कीमत पर मस्जिदों के अपमान की घटनाओं को सहन नहीं करेंगे और सरकार को ऐसी घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। ऐसी घटनाओं से मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। हालांकि, संविधान में हर व्यक्ति को जुलूस निकालने की आजादी है, लेकिन इन जुलूसों के दौरान जिस तरह से मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद साएम मेहदी नकवी ने कहा कि पिछले एक दशक में समाज दुश्मन ताकतों की ओर से मस्जिदों पर पथराव, उनकी दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखने और उनमें घुसकर एक विशेष धर्म से संबंधित झंडे लगाने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक भाषण दिए जाते हैं। हैरानी की बात है कि प्रशासन दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता। वक्फ संपत्ति का उल्लेख करते हुए बोर्ड ने कहा कि ये संपत्तियां हमारी आने वाली नस्लों की अमानत हैं और मुसलमान हर कीमत पर उनकी रक्षा करेंगे। बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर विचार करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की कार्यवाही पर भी सख्त नाराजगी प्रकट की है। बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि जेपीसी को उन्हीं संगठनों से राय मांगनी चाहिए थी, जिनका वक्फ से सीधा संबंध हो। हालांकि, जेपीसी के अध्यक्ष बहुसंख्यक समाज के हाथों में खेल रहे हैं और वे ऐसे संगठनों से भी राय मांग रहे हैं, जिनका वक्फ से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के मस्जिदों के सर्वे पर रोक लगाने से संबंधित फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे सांप्रदायिक सद्भावना में बढ़ोतरी होगी।

शिया बोर्ड ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि गाजा में युद्धविराम घोषित किया जाए। बोर्ड ने हाल ही में सीरिया में हुए सत्ता परिवर्तन की आलोचना करते हुए कहा कि एक साजिश के

तहत बशर अल-असद की शिया सरकार का तख्ता पलटा गया। इसका नेतृत्व सुन्नियों के एक आतंकवादी संगठन हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के प्रमुख अबू मोहम्मद अल-जुलानी ने किया। बोर्ड ने कहा है कि सीरिया में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके कारण शियाओं का जीवन और उनके धार्मिक स्थल खतरे में पड़ गए हैं। बोर्ड ने संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से अपील की है कि वे सीरिया में शियाओं के पवित्र स्थलों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। इनमें हजरत जैनब और हजरत शकीना की कब्रें भी शामिल हैं।

हिंदुस्तान (28 दिसंबर) के अनुसार मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में जमीयत उलेमा का एक अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया। मौलाना मदनी ने कहा कि मुसलमानों को मस्जिदों और वक्फ संपत्ति की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वक्फ संपत्ति में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुसंख्यक समाज का एक सांप्रदायिक वर्ग मुसलमानों की खरबों रुपये की वक्फ संपत्ति को हड़पना चाहता है। देश के मुसलमान इसका डटकर विरोध करेंगे।

उर्दू टाइम्स (17 दिसंबर) के अनुसार आंध्र प्रदेश के कडपा में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से 'संविधान बचाओ सम्मेलन' का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक वक्फ संपत्ति की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और अगर संविधान में कोई संशोधन करने का प्रयास किया गया तो देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मांग की कि वे मोदी सरकार पर यह दबाव डालें कि वह वक्फ संशोधन विधेयक को वापस ले ले। अगर मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती है तो तेलुगु देशम पार्टी को मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए।

एतेमाद (29 दिसंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की ओर से हैदराबाद में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में दलितों से अपील की गई कि वे अपने अधिकारों के लिए मुसलमानों के साथ मिलकर बहुसंख्यक समाज से युद्ध करें। एआईएमआईएम के विधायक मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि भाजपा व आरएसएस दलितों और मुसलमानों से संविधान में बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनना चाहते हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ दल अल्पसंख्यक और दलित विरोधी है। वह बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलकर इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहती है। मुसलमानों और दलितों को मिलकर इन प्रयासों का विरोध करना चाहिए। इस अवसर पर यह निर्णय किया गया कि देशभर में पूरी गति से दलित-मुस्लिम एकता अभियान को चलाया जाए।

चंदन गुप्ता हत्याकांड के 28 दोषियों को उम्रकैद

अवधनामा (4 जनवरी) के अनुसार चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 26 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। उल्लेखनीय है कि चंदन गुप्ता के पिता ने अपने पुत्र की हत्या के बाद एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिन दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है उनमें आसिफ कुरैशी, असलम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बब्लू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु, इमरान कय्यूम, आसिफ जिमवाला, वासिफ, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर सिद्दीकी और जाहिद उर्फ जग्गा शामिल हैं।

आरोपियों ने इस अदालत की कानूनी स्थिति पर सवाल खड़ा करते हुए मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने से संबंधित एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे रद्द कर दिया था। अदालती फैसले पर टिप्पणी करते हुए चंदन गुप्ता के पिता ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है। गौरतलब है कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में विश्व हिंदू परिषद की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। कुछ लोगों ने इस यात्रा का विरोध किया था। जब यह यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही थी तो उस पर हमला कर दिया गया था। इस हमले में 22 वर्षीय युवक चंदन गुप्ता की मौत हो गई थी। चंदन गुप्ता विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था और उसकी हत्या से उत्तर प्रदेश में भारी सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था।

अदालत ने कहा है कि चंदन की हत्या एक गंभीर प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। अगर इसे सख्ती से नहीं रोका गया तो इस तरह की अतिवादी गतिविधियां अन्य लोगों की भी जान ले सकती हैं। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने यह दावा किया था कि चंदन गुप्ता को उसके ही साथियों की गोली लगी थी और उस पर किसी बाहरी व्यक्ति ने हमला नहीं किया था। उसने कहा कि तिरंगा यात्रा को निकालने के सवाल पर विभिन्न गुटों में होड़ थी। इसके कारण आपसी भिडंत हुई। इसके बाद गोली चली और चंदन गुप्ता की मौत हो गई। अदालत ने आरोपियों के वकील के इस दावे को निराधार करार देते हुए कहा कि जांच और गवाहों के बयान से यह साबित होता है कि चंदन गुप्ता की हत्या सुनियोजित थी और इस हमले में कई लोग शामिल थे।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणा

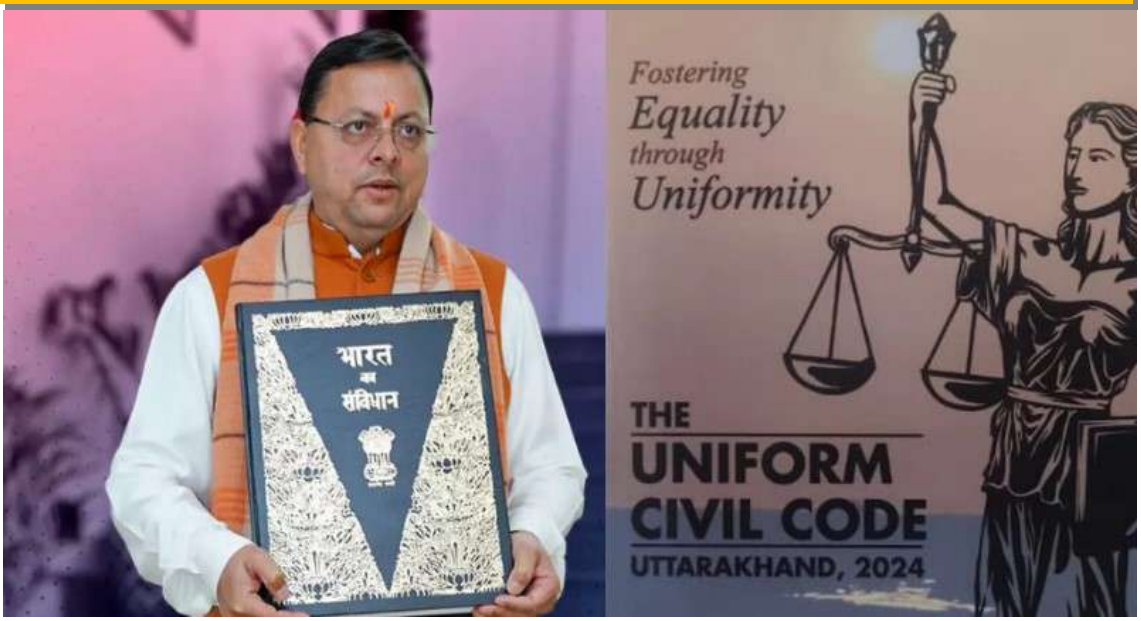

उर्दू टाइम्स (19 दिसंबर) के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि 2025 की शुरुआत में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि संसद में संविधान पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की थी कि उत्तराखंड के साथ-साथ भाजपा शासित सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने यह भी प्रकाश डाला था कि भाजपा शासित सरकारों द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं और क्या तैयारी की गई है।

पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में भाषण देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड भाजपा शासित राज्य सरकारों के सामने एक मॉडल के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भाजपा ने यह वायदा किया था कि अगर पार्टी फिर से सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। इस वायदे को पूरा करने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इस संबंध में सभी प्रशासकीय कदम उठा लिए गए हैं।

गौरतलब है कि 2022 में उत्तराखंड में भाजपा के फिर से सत्ता में आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी को 20 लाख सुझाव प्राप्त हुए थे। इस संबंध में कमेटी ने ढ़ाई लाख लोगों से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया था। इसके बाद 6 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक का प्रारूप राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक को विधानसभा से स्वीकृति मिलने के बाद इसे राजभवन के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया था। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी।

विश्व

पाकिस्तानी हवाई हमलों में 50 से अधिक अफगानों की मौत

रोजनामा सहारा (26 दिसंबर) के अनुसार तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पत्रकारों को बताया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने 24 दिसंबर की रात को अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बर्मल जिले में चार स्थानों पर बमबारी की, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक सरकारी बयान में अफगानिस्तान की भूमि पर पाकिस्तान के हालिया हमले की निंदा की है और इसे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बताया है। बयान में कहा गया है कि अफगान सरकार इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगी। यह हमारी संप्रभुता पर हमला है, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान की सीमा का निरंतर उल्लंघन करके मासूम लोगों को अपना निशाना बना रही है।

दूसरी ओर, पाकिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' को बताया कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान की भूमि पर स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए हैं। प्रवक्ता ने यह आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की भूमि से पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस ओर अफगानिस्तान सरकार का ध्यान कई बार दिला चुके हैं, लेकिन उसने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान सरकार आतंकवादियों को न सिर्फ शरण दे रही है, बल्कि उन्हें हथियार भी उपलब्ध करवा रही है। यह बेहद गंभीर मामला है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के इस आरोप का खंडन किया है और कहा है कि पाकिस्तान सरकार अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान खोजने में विफल रही है, इसलिए वह अफगानिस्तान सरकार को दोषी ठहरा रही है। हम आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल करने की अनुमति किसी को भी नहीं देंगे।

हिंदुस्तान (26 दिसंबर) के अनुसार अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस पाकिस्तानी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

मंत्रालय ने दावा किया कि पाकिस्तानी हवाई हमले में मरने वाले अधिकांश लोग पाकिस्तान के वजीरिस्तान क्षेत्र के शरणार्थी थे। अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारजामी ने कहा है कि पाकिस्तान का यह कहना बिल्कुल गलत है कि उसकी वायुसेना ने अफगानिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए हैं। हकीकत यह है कि इन हमलों के शिकार आम नागरिक हुए हैं और मरने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार तालिबान सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को यह निर्देश दिया है कि वे मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना उन्हें ट्रैक कर सकती है। उल्लेखनीय है कि यह हमला उस समय हुआ है जब पाकिस्तान के विशेष दूत मोहम्मद सादिक तालिबान सरकार के साथ काबुल में बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत का उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाना है। विश्लेषकों का कहना है कि इस हमले के कारण दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला रूक सकता है। इससे पहले भी सीमा अतिक्रमण को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेना के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं। इन झड़पों में लगभग 100 लोग मारे गए हैं। पिछले दो महीने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बंद है। इसके कारण दोनों देशों के व्यापार को भारी नुकसान हो रहा है।

गौरतलब है कि पाकिस्तानी वायुसेना ईरानी क्षेत्रों पर भी हमला कर चुकी है। तब भी पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उसने ईरान स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए हैं। इन हमलों में कई ईरानी नागरिक मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने पाकिस्तान से लगने वाली अपनी सीमा को बंद कर दिया था।

कौमी तंजीम (30 दिसंबर) के अनुसार अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी वायुसेना के हमले के जवाब में तालिबान सेना ने पाकिस्तान की चार सीमावर्ती चौकियों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के सूत्रों के अनुसार इस हमले में 22 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई घायल हो गए। पाकिस्तानी सूत्रों ने इस हमले की पुष्टि की है। बताया जाता है कि पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में कम-से-कम तीन तालिबान सैनिक मारे गए हैं।

पाकिस्तानी अखबार **जंग** (29 दिसंबर) के अनुसार अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारजामी ने कहा है कि हाल ही में एक पड़ोसी देश ने हमारी वायु सीमा का अतिक्रमण किया था। इसके जवाब में अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र से दुश्मन देश की अनेक सैनिक चौकियों को निशाना बनाया गया है। प्रवक्ता ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि काल्पनिक सीमा रेखा के पार हमले किए गए हैं। ख्वारजामी ने कहा कि यह काल्पनिक सीमा रेखा अंग्रेजों ने बनाई थी, जिसे हम मान्यता नहीं देते हैं। यह क्षेत्र पाकिस्तान का नहीं, बल्कि अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है। इस पर ब्रिटिश

शासन के जमाने में जबरन कब्जा किया गया था। ख्वारजामी के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि अफगान सरकार तथ्यों की अनदेखी कर रही है। डूरंड लाइन को दशकों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हम अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं।

हिंदुस्तान (29 दिसंबर) ने यह दावा किया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेना के बीच झड़पें जारी हैं। इन झड़पों में घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में पाकिस्तानी हमले के खिलाफ सैकड़ों अफगानों ने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। टेलीविजन नेटवर्क अल अरेबिया के अनुसार दोनों देशों के सैनिकों के बीच होने वाली झड़पों में तेजी आ रही है। हाल ही में काबुल में भारतीय दूतावास के समीप एक धमाका हुआ है। इस धमाके में छह लोग घायल हुए हैं। अफगान सरकार इस धमाके की जांच कर रही है।

मुंसिफ (27 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने यह आरोप लगाया है कि उसके देश में हो रही आतंकवादी घटनाओं का संचालन अफगानिस्तान से किया जा रहा है। पिछले महीने पाकिस्तान में हुई आतंकवादी घटनाओं में 270 लोग मारे गए थे। इनमें 70 सैनिक भी शामिल थे। शहबाज शरीफ के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान सरकार आतंकवादी घटनाओं को रोकने में विफल रही है। ■

बांग्लादेश तब्लीगी इज्तिमा में दो गुटों के बीच खूनी झड़पें

रोजनामा सहारा (19 दिसंबर) के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 20 किलोमीटर दूर टोंगी में विश्व इज्तिमा मैदान पर कब्जे को लेकर तब्लीगी जमात के दो गुटों में खूनी झड़पें हुई हैं। कहा जाता है कि इन झड़पों में कम-से-कम 10 लोग मारे गए हैं। जबकि तब्लीगी जमात (साद गुट) के प्रवक्ता ने इन झड़पों में अपने सात कार्यकर्ताओं के मारे जाने की पुष्टि की है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने यह दावा किया है कि इन झड़पों में कम-से-कम पांच लोग मारे गए हैं और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए इज्तिमा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस पूरे क्षेत्र को सेना के हवाले कर दिया गया है। सेना को यह निर्देश दिया गया है कि इस क्षेत्र में एक साथ दो से अधिक लोगों को इकट्ठा न होने दिया जाए। इसके अतिरिक्त हथियारों को अपने साथ ले जाने और नारे लगाने पर भी सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। सेना दोनों गुटों से संबंधित दंगाइयों को गिरफ्तार कर रही है। अब तक 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि ढाका में तब्लीगी जमात द्वारा हर वर्ष विश्व इज्तिमा का आयोजन किया जाता है। इस इज्तिमा में 20-25 लाख लोग हिस्सा लेते हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार इन झड़पों की शुरुआत 18 दिसंबर की सुबह तब हुई जब

बांग्लादेश तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना जुबैर अहमद के समर्थकों ने भारतीय तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद कांधलवी और उनके समर्थकों को इज्तिमा स्थल में दाखिल होने से रोकने का प्रयास किया। इसके बाद दोनों गुटों के बीच हिंसा की शुरुआत हो गई। बताया जाता है कि खूनी झड़पों का यह सिलसिला तीन घंटे तक चलता रहा। पुलिस ने जब इन झड़पों को रोकने का प्रयास किया तो तब्लीगी जमात के कार्यकर्ताओं ने उन पर ही धावा बोल दिया, जिसमें दो दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को बिगड़ता देख घटनास्थल पर सेना को बुलाना पड़ा।

गौरतलब है कि ढाका में विश्व तब्लीगी इज्तिमा के आयोजन का सिलसिला 1967 में शुरू हुआ था। शुरुआत में यह इज्तिमा एक दिन का होता था। बाद में भारी संख्या में लोग इस इज्तिमा में शामिल होने लगे तो इसकी अवधि बढ़ाकर तीन दिनों तक कर दी गई। उल्लेखनीय है कि इस्लाम बांग्लादेश का सबसे बड़ा धर्म है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान बांग्लादेश में रहते हैं। मौलाना साद और मौलाना जुबैर गुट के बीच विवाद की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसके बाद तत्कालीन शेख हसीना सरकार ने संभावित हिंसा को देखते हुए दोनों गुटों को अलग-अलग तिथियों पर इज्तिमा का आयोजन करने की अनुमति दी थी।

ढ़ाका से प्रकाशित अंग्रजी अखबार **द डेली स्टार** (21 दिसंबर) के अनुसार पुलिस ने मुआज बिन नूर को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुआज का संबंध साद गुट से बताया जाता है। टोंगी वेस्ट पुलिस थाने के प्रभारी इस्कंदर हबीबुर रहमान ने बताया कि इस दंगे के सिलसिले में पांच मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें से तीन मुकदमे बांग्लादेश के तब्लीगी नेता मौलाना जुबैर अहमद के समर्थकों ने दर्ज कराए हैं। जुबैर गुट के प्रवक्ता हबीबुल्लाह रेहान ने संवाददाताओं को बताया कि तब्लीगी जमात राजनीति से दूर रहकर अपने आप को सिर्फ इस्लाम और धार्मिक मामलों तक ही सीमित रखता है। जबकि मौलाना साद को एक पड़ोसी देश की सरकार ने बांग्लादेश भेजा था ताकि यहां पर हिंसा भड़काई जा सके। इसी को देखते हुए हम उनके इस इज्तिमा में आने का विरोध कर रहे थे। हमने अपने समर्थकों को यह निर्देश दिया था कि वे मौलाना साद या उनके किसी समर्थक को इज्तिमा में घुसने न दें, क्योंकि वे राजनेताओं के हाथ में खेल रहे हैं।

बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले साल दोनों गुटों को अलग-अलग तिथि पर इज्तिमा का आयोजन करने की अनुमति दी गई थी। जुबैर गुट ने 31 जनवरी से 2 फरवरी तक इज्तिमा का आयोजन किया था। जबकि साद गुट ने 7 से 9 फरवरी तक इज्तिमा का आयोजन किया था। इस बार गृह मंत्रालय यह प्रयास कर रहा था कि इज्तिमा में दंगों को रोकने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। इस संदर्भ में सरकार दोनों गुटों से बातचीत भी कर रही थी। इसी बीच मौलाना साद अपने समर्थकों के साथ दिल्ली से ढाका पहुंच गए। इससे स्थिति बिगड़ गई और दोनों गुटों के बीच हुई झड़पों में कई लोग मारे गए। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने मौलाना साद को वापस भारत भेजने का फैसला किया है।

पृष्ठभूमि : तब्लीगी जमात विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन है। इसकी शाखाएं दुनिया के 140 देशों में फैली हुई हैं। इसके अनुयायियों की संख्या 30 करोड़ से भी अधिक बताई जाती है। जमात के नेताओं का दावा है कि उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है और उनकी गतिविधियां सिर्फ विश्वभर में इस्लाम के प्रचार-प्रसार तक ही सीमित हैं। जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई के अनुसार तब्लीगी जमात जिहादी तैयार करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। विश्व के अनेक भागों में हुई आतंकवादी घटनाओं के पीछे इस संगठन का हाथ बताया जाता है। तब्लीगी जमात की स्थापना 1926 में भारत में की गई थी। जमात के प्रवक्ताओं के अनुसार जब 1920 में आर्य समाज के एक सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद ने मुसलमानों को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप तब्लीगी जमात अस्तित्व में आया था। इसके संस्थापक मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी थे। कांधलवी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा कांधला के रहने वाले थे। उनका संबंध वहाबी संप्रदाय से था। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में इस्लामिक शिक्षा ग्रहण की थी।

जमात का मुख्यालय सबसे पहले देश की राजधानी नई दिल्ली की बस्ती निजामुद्दीन स्थित बंग्लेवाली मस्जिद में स्थापित किया गया था। देश के विभाजन के बाद भारत के अतिरिक्त इसका मुख्यालय पाकिस्तान के रायविंड और बांग्लादेश के टोंगी में भी स्थापित किया गया। खास बात यह है कि कई इस्लामिक देशों में तब्लीगी जमात की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें सऊदी अरब, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान प्रमुख हैं। मौलाना मोहम्मद इलियास कांधलवी के निधन के बाद इस संगठन का नेतृत्व उनके पुत्र मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांधलवी ने संभाला। यूसुफ के निधन के बाद उनके पुत्र मौलाना इनामुल हसन कांधलवी इस संगठन के अमीर बने। उनके निधन के बाद उनके पुत्र जुबैर उल हसन इस संगठन के प्रमुख बने।

मार्च 2014 में जुबैर उल हसन का निधन हो गया। इसके बाद जब जुबैर उल हसन के बेटे मौलाना जुहैर उल हसन कांधलवी को इस संगठन का नया प्रमुख बनाया गया तो इसका विरोध शुरू

हो गया और तब्लीगी जमात तीन धड़ों में विभाजित हो गया। एक गुट की जिम्मेवारी मौलाना इलियास के परपौत्र मौलाना साद कांधलवी ने संभाल ली। जबकि तीसरे गुट का कार्यभार सात प्रमुख नेताओं की एक निगरानी समिति ने संभाला। बाद में मौलाना साद के गुट में भी विद्रोह हो गया और इसके एक गुट की बागडोर संभालने के लिए शूरा-ए-अमल का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नवी मुंबई स्थित एक मस्जिद में स्थापित किया गया।

तब्लीगी जमात कोरोना काल के दौरान सुर्खियों में आया। तब सरकार ने यह आरोप लगाया था कि तब्लीगी जमात के इज्तिमा में भाग लेने वालों के कारण देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। इसके बाद सरकार ने तब्लीगी जमात के मुख्यालय निजामुद्दीन स्थित बंग्लेवाली मस्जिद को सील कर दिया था और जमात के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में मौलाना साद ने इस प्रतिबंध को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर बंग्लेवाली मस्जिद में स्थित तब्लीगी जमात के मुख्यालय को मौलाना साद के हवाले कर दिया गया था।

बांग्लादेश द्वारा भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग

रोजनामा सहारा (24 दिसंबर) के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत सरकार से मांग की है कि वह बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को उसके हवाले कर दे ताकि भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया जा सके। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने इस खबर की पुष्टि की है और कहा है कि बांग्लादेश सरकार ने इस संदर्भ में भारतीय विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि 2013 में दोनों देशों के बीच एक प्रत्यर्पण संधि हुई है। इस संधि में अपराधियों को एक दूसरे देश के हवाले करने की कानूनी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि इस संधि के तहत भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश सरकार के हवाले करना होगा।

इससे पहले बांग्लादेश सरकार ने इंटरपोल से अनुरोध किया था कि वह शेख हसीना की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे ताकि उन्हें गिरफ्तार करके बांग्लादेश सरकार के हवाले किया जा सके। बांग्लादेश सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा था कि

हमारे देश के अपराधी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हुए हों, हम उन्हें वापस लाकर अदालत में पेश करेंगे ताकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। 17 अक्टूबर को बांग्लादेश सरकार द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना और 45 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। इनमें शेख हसीना के पुत्र साजिब वाजेद और हसीना मंत्रिमंडल के अनेक पूर्व मंत्री शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में हसीना सरकार के खिलाफ हुए राष्ट्रव्यापी हिंसक प्रदर्शनों के कारण 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत चली गई थीं। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार ने यह दावा किया था कि इन प्रदर्शनों में एक हजार से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं। शेख हसीना के खिलाफ 225 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें हत्या के 194 मुकदमे भी शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के कई आतंकवादी 2013 से बांग्लादेश में छिपे हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक बांग्लादेश सरकार के इस अनुरोध पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जानकार सूत्रों से पता चला है कि अगर किसी राजनेता के खिलाफ इस तरह के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं तो भारत संबंधित राजनेता को बांग्लादेश के हवाले करने से इंकार कर सकता है।

ढाका ट्रिब्यून ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के कारण बांग्लादेश सरकार ने 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के नेता अनूप चेतिया को भारत के हवाले किया था। इस संधि के तहत भारत सरकार भी अब तक कई लोगों को बांग्लादेश के हवाले कर चुकी है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि 2016 में इस संधि में संशोधन किया गया था। संशोधित संधि के तहत आरोपियों को संबंधित देश के हवाले करने के लिए कोई

प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अदालत द्वारा जारी वारंट ही काफी है।

औरंगाबाद टाइम्स (26 दिसंबर) के अनुसार शेख हसीना के पुत्र साजिब वाजेद ने आरोप लगाया है कि यूनुस सरकार राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना के तहत न्यायपालिका को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और अपने विरोधियों के खिलाफ झूठे आरोप लगा रही है।

मुंसिफ (24 दिसंबर) के अनुसार नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी के अध्यक्ष बॉबी हज्जाज ने ढाका उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि शेख हसीना ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने के लिए रिश्वत ली थी। 12.65 अरब डॉलर की लागत से इस संयंत्र को स्थापित किया गया था। रूस सरकार ने इसके लिए 90 प्रतिशत धनराशि बांग्लादेश सरकार को कर्ज के रूप में दी थी। हज्जाज ने आरोप लगाया है कि शेख हसीना और उनके परिवारजनों ने इस संयंत्र के लिए मंजूर धनराशि में से पांच अरब डॉलर का गबन किया था।

इंकलाब (25 दिसंबर) के अनुसार रूस सरकार ने इस आरोप का खंडन किया है कि जिस कंपनी को इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने का ठेका दिया गया था उससे शेख हसीना या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने रिश्वत ली थी। रूस सरकार ने कहा है कि यह आरोप बेबुनियाद और झूठा है।

हिंदुस्तान (25 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बांग्लादेश सरकार हर कीमत पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहती है। बांग्लादेश की मुक्ति के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं। अब मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं के कथित उत्पीड़न और मंदिरों पर हमले के खबरों को उछाला जा रहा है। इस संबंध में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा देशभर में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन कर रही है। हालांकि, जब भारत सरकार ने इस मामले को बांग्लादेश सरकार के सामने उठाया तो वहां की सरकार ने मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए उसे दो टूक शब्दों के कहा कि पहले वह अपने देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था करे। इसके बाद बांग्लादेशी हिंदुओं के मामले को उठाए। बांग्लादेश की सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश सरकार के हवाले नहीं किया तो दोनों देशों के संबंधों में और भी कटुता आ जाएगी। अब देखना यह है कि मोदी सरकार इस संबंध में क्या फैसला लेती है।

उर्दू टाइम्स (17 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विजय दिवस के मौके पर जो संदेश बांग्लादेश सरकार को भेजा था उसे उसने पसंद नहीं किया है। समाचारपत्र पत्र ने हैरानी प्रकट की है कि मोदी सरकार ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण वाली तस्वीर को भारत के सेना मुख्यालय से हटा दिया है। ऐसे में विजय दिवस का मनाया जाना किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

कौमी तंजीम (26 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि शेख हसीना के मामले में मोदी सरकार ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है, जिससे निकल पाना संभव नजर नहीं आता है। न तो वह शेख हसीना को बांग्लादेश सरकार के हवाले कर सकती है और न ही बांग्लादेश सरकार के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ सकती है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (26 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बांग्लादेश सरकार की इस मांग के कारण दिल्ली और ढाका के बीच एक नए विवाद की शुरुआत हो गई है। इस विवाद का परिणाम क्या होगा इस पर फिलहाल कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है। भारत सरकार को अपना हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा, क्योंकि यह मामला बेहद जटिल है।

अमेरिका और जर्मनी में इस्लामिक आतंकवादियों का कहर

अमेरिका और जर्मनी में इस्लामिक आतंकवादी कहर ढा रहे हैं। दोनों देशों में इस्लामिक आतंकवादियों ने क्रिसमस और नव वर्ष का जश्न मना रहे दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है।

अवधनामा (2 जनवरी) के अनुसार अमेरिका में नव वर्ष के जश्न में शामिल लोगों पर एक आतंकवादी ने हमला कर दिया। इस आतंकवादी ने 15 लोगों को ट्रक से कुचलकर मार डाला और 200 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। इस जिहादी ने अपने ट्रक में कुख्यात इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का झंडा रखा हुआ था। इसके बाद इस आतंकवादी ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस गोलीबारी में कई लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। घायलों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। बाद में पुलिस ने इस आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया।

इंकलाब (2 जनवरी) के अनुसार यह आतंकवादी हमला अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में हुआ। यहां पर हजारों लोग नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे और 300 से अधिक पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। अचानक एक व्यक्ति एक ट्रक चलाते हुए आया और उसने लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह ट्रक से उतर गया और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। पुलिस के अनुसार हमलावर की पहचान 42 वर्षीय शम्सुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है। यह व्यक्ति अफगान मूल का था और इसे अमेरिका में एक शरणार्थी के रूप में शरण दी गई थी। जब्बार ने लगभग एक दशक तक अमेरिकी सेना में नौकरी की थी। वह अमेरिकी सैनिक के रूप में लगभग एक साल तक अफगानिस्तान में भी तैनात रहा। जब्बार ने दो शादियां की थी, लेकिन दोनों पत्नियां उससे अलग हो गई थीं। अमेरिकी पुलिस उसके आतंकवादी संपर्कों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। एफबीआई सूत्रों के अनुसार घटनास्थल से कुछ बम भी बरामद हुए हैं।

अमेरिका में नव वर्ष के मौके पर ही एक अन्य आतंकवादी घटना हुई है। लास वेगास में ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर एक ट्रक में भीषण विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में कई लोग घायल हो गए हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने इस घटना के पीछे भी आतंकवादियों के हाथ होने की संभावना व्यक्त की है।

रोजनामा सहारा (22 दिसंबर) के अनुसार जर्मनी के मैगडेबर्ग स्थित क्रिसमस बाजार में मौजूद भीड़ पर एक इस्लामिक आतंकवादी ने अपनी कार चढ़ा दी। इस हमले में कम-से-कम सात लोग मौके मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें 20 भारतीय नागरिक भी बताए जाते हैं। पुलिस ने इस कार चालक को अपनी हिरासत में ले लिया है। इस व्यक्ति का

नाम तालेब अल-अब्दुलमोहसेन है और वह सऊदी अरब का मूल निवासी है।

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी सरकार ने यह पुष्टि की है कि दोषी व्यक्ति सऊदी अरब का नागरिक है। उसे एक इस्लामिक आतंकवादी गुट की गतिविधियों में लिप्त पाया गया था, इसलिए सऊदी अरब सरकार ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया था। बाद में उसने जर्मनी में राजनीतिक शरण प्राप्त कर ली थी। सऊदी सरकार ने यह भी दावा किया कि इस व्यक्ति की खतरनाक पृष्ठभूमि के बारे में जर्मनी की सरकार को विधिवत सूचना दी गई थी, लेकिन जर्मनी के नरम कानूनों के कारण वहां की सरकार दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सकी। इसका लाभ उठाकर उसने वहां के ईसाइयों के खून की होली खेली है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि जर्मन सरकार आप्रवासियों से संबंधित कानून में संशोधन करके उसे और कड़ा बनाएगी। उन्होंने कहा है कि इस हमले में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि अस्पताल में भर्ती 40 घायलों की हालत नाजुक बताई जाती है। मैगडेबर्ग के पुलिस अधिकारी माइकल रीफ ने कहा है कि हमलावर ने अपनी कार को जानबूझकर क्रिसमस मना रहे लोगों की भीड़ पर चढ़ा दी। उसने लोगों की हत्या करने की योजना से ही इस भीड़-भाड़ वाले बाजार को चुना था। उसने चेतावनी के बावजूद अपनी कार को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया और लोगों को कुचलता चला गया।

एक अन्य समाचार के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने इस हमले की निंदा की है। सऊदी सरकार ने कहा है कि हमला करने वाला व्यक्ति सऊदी अरब का नागरिक है और वह पेशे से एक डॉक्टर है। उसे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण 2006 में सऊदी अरब से निष्कासित कर दिया गया था। तब से वह जर्मनी में रह रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले 2016 में भी एक जुनूनी इस्लामी अतिवादी अनीस अमरी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में स्थित क्रिसमस बाजार में एकत्रित भीड़ पर जानबूझकर एक ट्रक चढ़ा दिया था, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ट्यूनीशियाई मूल के इस चालक ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।

जर्मनी की सरकार ने यह घोषणा की है कि वह गुप्तचर एजेंसियों से इस घटना की जांच करवा रही है ताकि इस घटना से जुड़े हुए सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि कुछ जुनूनी इस्लामी अतिवादी जर्मनी के वर्तमान शासन प्रणाली का तख्ता पलटकर देश में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करना चाहते हैं। जर्मनी की जनता इस तरह की हरकत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। ■

अफगानिस्तान में अब खिड़कियों पर भी प्रतिबंध

सियासत (31 दिसंबर) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने घरों में खिड़कियां बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम शरिया के तहत उठाया गया है। तालिबान सरकार की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह दावा किया गया है कि रसोई और आंगन में काम करने वाली महिलाओं या कुओं से पानी भरती महिलाओं को देखने से अश्लीलता को बढ़ावा मिल सकती है। यह इस्लाम के खिलाफ है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने आदेश जारी किया है कि घरों में ऐसी खिड़कियों को बंद कर दिया जाए, जिनसे पड़ोसियों के घरों की महिलाएं काम-काज करती नजर आती हों। मकान मालिकों को यह आदेश दिया गया है कि वे तमाम खिड़कियों को ईंट और सीमेंट से बंद कर दें। इस संबंध में नगरपालिकाओं और पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

उर्दू टाइम्स (1 जनवरी) के अनुसार तालिबान सरकार ने महिला अधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे सभी देशी और विदेशी संगठनों को बंद करने का आदेश दिया है। तालिबान सरकार ने इन संगठनों को महिलाओं को नौकरी पर न रखने का निर्देश दिया था, लेकिन कई संगठनों ने इस निर्देश का उल्लंघन किया था। भविष्य में किसी भी देशी या विदेशी संगठन को महिलाओं के क्षेत्र में किसी तरह की गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने इन सभी संगठनों का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। तालिबान शासकों ने कहा है कि यह फैसला इसलिए किया गया है, क्योंकि अफगानिस्तान की महिलाओं में पर्दा न करने, बुर्का न पहनने और सिर न ढकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तालिबान सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि भविष्य में अफगानिस्तान की महिलाएं और लड़कियां नर्सिंग व मेडिकल की शिक्षा लेने हेतु किसी भी संस्थान में अपना नामांकन नहीं करवा सकती हैं। ■

सीरिया में शिया–सुन्नी गृहयुद्ध भड़का

इंकलाब (27 दिसंबर) के अनुसार सीरिया की कार्यवाहक सरकार ने यह स्वीकार किया है कि देश के विभिन्न भागों में अभी भी अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद के समर्थक सरकारी सेना पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों में अब तक 14 लोग मारे गए हैं। बीबीसी न्यूज के अनुसार सरकारी सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों भूमध्य सागर के तट पर स्थित टारटस बंदरगाह के समीप युद्ध भड़क उठा है। जो लोग कार्यवाहक सरकार का विरोध कर रहे हैं उनका संबंध बशर अल-असद के अलावी कबीला से है। यह एक शिया कबीला है। बीबीसी ने कहा है कि सीरिया में शिया-सुन्नी संघर्ष दिन-प्रतिदिन फैल रहा है।

सियासत (27 दिसंबर) के अनुसार सीरिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक शिया दरगाह पर हमले के बाद उसमें तोड़फोड़ की गई है। इसके खिलाफ शियाओं ने सीरिया के नगर टारटस और लताकिया में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त बशर अल-असद के पैतृक शहर करदाहा और होम्स के अनेक क्षेत्रों में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारी 'सुन्नियों हम शांति चाहते हैं, हमारी दरगाहों को निशाना मत बनाओ' के नारे लगा रहे थे। सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि सेना ने देश के अनेक भागों में कर्फ्यू लगा दिया है ताकि वर्तमान सरकार के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को नियंत्रित किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुन्नियों ने अलेप्पो और मेसालून में दो शिया दरगाहों को तबाह कर दिया है। जब शियाओं ने इसका विरोध किया तो सरकारी सेना ने कम-से-कम 12 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी।

इंकलाब (27 दिसंबर) के अनुसार सरकारी सैनिक जब सीरिया की सबसे कुख्यात जेल सेदानाया के एक उच्चाधिकारी को दमिश्क में गिरफ्तार करने पहुंचे तो उन पर बशर अल-असद के सशस्त्र समर्थकों ने हमला कर दिया, जिसमें 10 सरकारी सैनिक मारे गए। सैन्य संचालन विभाग ने यह स्वीकार किया है कि पुरानी सरकार के समर्थकों ने देश के कम-से-कम दो दर्जन स्थानों पर सरकारी सेना पर हमले किए हैं। इन हमलों मे कई सैनिक मारे गए हैं। अल अरेबिया के संवाददाता के अनुसार अलेप्पो स्थित

शिया दरगाह अबू अब्दुल्ला अल-हुसैनी अल-खासिबी पर सरकारी सेना के हमले के बाद सशस्त्र लोगों की सेना के साथ झड़पें हुईं। इन झड़पों में कई लोग मारे गए। इस संदर्भ में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें हमलावरों को दरगाह में तोड़फोड़ करते और उसमे आग लगाते हुए दिखाया गया है।

सीरिया के गृह मंत्रालय ने यह दावा किया है कि यह वीडियो पुराना है और वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए विदेशी एजेंसियों ने इसका प्रसारण किया है। रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि सीरिया के पूर्वी क्षेत्र में स्थित विद्रोहियों को कुचलने के लिए राजधानी दमिश्क से सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारी सेना ने विद्रोहियों के एक अड्डे को अपने घेरे में ले लिया है और दोनों ओर से हुई गोलीबारी में कई लोग मारे गए हैं। बशर अल-असद के समर्थक टारटस, लताकिया और होम्स के एक दर्जन स्थानों पर सरकारी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। इसके कारण होम्स, बनियास, टारटस और जबाला में कर्फ्यू लगा दिया गया है। विद्रोहियों को कुचलने के लिए सीरिया की कार्यवाहक सरकार ने नया फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

इंकलाब (1 जनवरी) के अनुसार सीरिया के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कई स्थानों पर अमेरिका समर्थक कुर्द गठबंधन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एसडीएफ) और सरकारी सेना के बीच खूनी संघर्ष हो रहा है। अमेरिका के नेतृत्व में गठित अंतरराष्ट्रीय गठबंधन ने सरकारी सेना से लड़ने वाले एसडीएफ को भारी मात्रा में सैन्य सामग्री भेजी है। सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि अमेरिका द्वारा रक्का और कोबानी में बख्तरबंद वाहन और टैंक भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने तुर्किये पर यह दबाव डाला है कि वह एसडीएफ के अड्डों पर हमला न करे, लेकिन तुर्किये ने इसे मानने से इंकार कर दिया है। तुर्किये ने कहा है कि कुर्द विद्रोहियों के पास आत्मसमर्पण करने के अतिरिक्त अब कोई अन्य रास्ता नहीं बचा है।

एक अन्य समाचार के अनुसार तुर्किये की सेना और कुर्दों के बीच लड़ाई भड़क उठी है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' के अनुसार हाल ही में इन झड़पों में 50 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। कुर्दों को अमेरिका की ओर से निरंतर सैन्य सामग्री भेजी जा रही है। गौरतलब है कि 2015 में अमेरिका ने एसडीएफ का गठन किया था और उसने इसका इस्तेमाल इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस का मुकाबला करने के लिए किया था। तुर्किये ने यह आरोप लगाया है कि इस संगठन के एक प्रमुख अंग पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट (वाईपीजी) का संबंध विद्रोही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) से है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कुर्द सेना और सीरिया के सरकारी सैनिकों के बीच युद्ध हो रहा है। इस युद्ध को रोकने के सभी प्रयास विफल हो गए हैं। सीरिया के अलेप्पो क्षेत्र में कुर्दों और सरकारी सेना के बीच युद्ध जारी है। इसके कारण फरात नदी पर एक पुल के नजदीक स्थित दो रडार केंद्र और कई टैंक तबाह हो गए हैं। ब्रिटिश मीडिया के अनुसार इस क्षेत्र में कुर्दों और सरकारी सेना के बीच पिछले तीन सप्ताह से युद्ध हो रहा

है। सीरिया में अभी भी अमेरिका के लगभग दो हजार सैनिक मौजूद हैं। ये सैनिक एसडीएफ के साथ मिलकर आईएसआईएस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं।

कौमी तंजीम (29 दिसंबर) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने आरोप लगाया है कि विदेशी शक्तियां सीरिया में हस्तक्षेप कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सीरियाई जनता को अपने भविष्य का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए और विदेशी शक्तियों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि इन दिनों ईरान के विदेश मंत्री चीन में हैं। उन्होंने यह बयान चीन के सरकारी अखबार 'पीपुल्स डेली' को दिए एक इंटरव्यू में दिया है। अराघची ने आरोप लगाया है कि सीरिया की कार्यवाहक सरकार विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है।

अवधनामा (2 जनवरी) के अनुसार इस्लामाबाद स्थित ईरानी राजदूत डॉ. रेजा अमीरी मोगादम ने दावा किया है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी ताकतें मुस्लिम देशों को शिया-सुन्नी आधार पर आपस में लड़वाने की साजिश रच रही हैं। उन्होंने चिंता प्रकट की कि ये साम्राज्यावादी ताकतें अपने इस लक्ष्य में सफल हो रही हैं।

सियासत (22 दिसंबर) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कहा है कि उनका देश गृहयुद्ध के कारण तबाह हुए सीरिया की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु हर तरह की सहायता देने के लिए तैयार है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सीरिया की नई सरकार के साथ तुर्किये के संबंध मजबूत होंगे। एर्दोगन ने मांग की कि विभिन्न विदेशी ताकतों ने सीरिया पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं उन्हें वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के प्रमुख अबू मोहम्मद अल-जुलानी सभी इस्लामिक देशों में एकता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

उर्दू टाइम्स (25 दिसंबर) के अनुसार एचटीएस के प्रमुख अल-जुलानी ने यह दावा किया है कि सीरिया में संघर्षशील सभी सशस्त्र गुट सीरिया की सशस्त्र सेना में शामिल होने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सशस्त्र गुट भविष्य में सीरियाई रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करेंगे और वे अपने हथियार सरकार के हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सीरिया अफगानिस्तान के रास्ते पर न चले और देश में गृहयुद्ध समाप्त हो जाए।

मुंसिफ (31 दिसंबर) के अनुसार अबू मोहम्मद अल-जुलानी ने कहा है कि सऊदी अरब के शासकों के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई है। सऊदी अरब सीरिया के नवनिर्माण में सहयोग देने के लिए तैयार हो गया है। अल-जुलानी ने कहा कि मैं सऊदी अरब में पैदा हुआ था, इसलिए मेरा उस देश से गहरा लगाव है। मुझे विश्वास है कि सीरिया के नवनिर्माण में सऊदी अरब की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

एतेमाद (30 दिसंबर) के अनुसार अल-जुलानी ने कहा कि सीरिया की आजादी की लड़ाई में सिर्फ उनकी भूमिका नहीं है। इसकी आजादी में वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने कई सालों तक तानाशाह बशर अल-असद के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि सीरिया में तत्काल चुनाव करवाना संभव नहीं होगा। सबसे पहले देश

का नया संविधान तैयार किया जाएगा। इसमें कम-से-कम तीन साल लगेंगे। इसके बाद ही देश में आम चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुर्द लोग सीरिया के अभिन्न अंग हैं और हम किसी भी कीमत पर देश को विभाजित नहीं होने देंगे। जो विदेशी शक्तियां सीरिया की एकता को भंग करना चाहती हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी।

उर्दू टाइम्स (27 दिसंबर) के अनुसार सीरिया के गृह मंत्री मोहम्मद अब्दुल रहमान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे, जो सीरिया की एकता के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि जो लोग विदेशी ताकतों के इशारे पर सीरिया में अशांति फैला रहे हैं उन्हें सख्ती से कुचल दिया जाएगा। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि सीरिया में संघर्षशील सभी सशस्त्र गुट अपने हथियार सरकार के हवाले कर दें ताकि गृहयुद्ध की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाए।

उर्दू टाइम्स (23 दिसंबर) के अनुसार दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास के एक कर्मचारी की तब हत्या कर दी गई जब वे अपनी कार से सफर कर रहे थे। ईरान की सरकार ने सीरिया से अनुरोध किया है कि वह हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

सियासत (23 दिसंबर) के अनुसार तुर्किये के गृह मंत्री अली येर्लिकाया ने दावा किया है कि पिछले एक महीने में एक लाख 24 हजार सीरियाई शरणार्थी तुर्किये से सीरिया लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी यह सिलसिला जारी है और हर दिन औसतन 11 हजार शरणार्थी स्वदेश लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीकेके की ओर से अशांति फैलाना का प्रयास किया जा रहा है और हम इन आतंकवादियों को सख्ती से कुचलने के लिए कटिबद्ध हैं। पिछले साल 800 से अधिक आतंकवादियों का सफाया किया जा चुका है और लगभग दो हजार संदिग्ध आतंकवादियों को हिरासत में लिया गया है।

हिंदुस्तान (19 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जिस तरह से अमेरिका सीरिया में अपने पैर पसारने का प्रयास कर रहा है वह भविष्य में इस्लामिक एकता के लिए हानिकारक साबित होगा। समाचारपत्र ने हैरानी प्रकट की है कि बशर अल-असद की सेना ने बिना युद्ध किए अचानक एचटीएस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि रूस पिछले 50 सालों से सीरिया की पुरानी सरकार का समर्थन करता आ रहा था और बशर अल-असद की सरकार ईरान व रूस के समर्थन पर ही टिकी हुई थी। अचानक ये दोनों देश बशर अल-असद का समर्थन करने से पीछे क्यों हट गए? यह एक ऐसा रहस्य है जिसका कोई उत्तर नजर नहीं आ रहा है।

सियासत (16 दिसंबर) के अनुसार एचटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद अल-जुलानी ने दावा किया है कि इजरायल सीरिया पर हमला करने के लिए झूठे बहाने की तलाश कर रहा है।

इजरायल सीरिया के एक हिस्से को हड़पना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें युद्ध में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि हम अपने देश का नवनिर्माण करना चाहते हैं। दूसरी ओर, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्पष्ट किया है कि हमें सीरिया के साथ युद्ध करने में कोई रुचि नहीं है। गौरतलब है कि सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल-असद 8 दिसंबर 2024 को अपने देश छोड़कर रूस भाग गए थे। इजरायल तब से अब तक कई बार सीरिया के विभिन्न क्षेत्रों पर हमले कर चुका है। इजरायल सरकार के अनुसार इन हमलों का लक्ष्य सीरिया की सेना की आक्रामकता को खत्म करना और इजरायल की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है।

सीरिया में एक लाख से अधिक लोगों की हत्या का आरोप

इंकलाब (30 दिसंबर) के अनुसार सीरियन नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स (एसएनएचआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार बशर अल-असद के शासनकाल में सीरिया में एक लाख 12 हजार से अधिक नागरिकों के लापता होने की पुष्टि हुई है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासनकाल में सरकार के विरोधी माने जाने वाले इन लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। इस संगठन ने दावा किया है कि बशर अल-असद के शासन के पतन के बाद सीरिया की विभिन्न जेलों में बंद 60 हजार कैदियों को रिहा कर दिया गया है। इनमें से कई लोग पिछले चार दशक से सीरिया की विभिन्न जेलों में बंद थे। उनके खिलाफ कभी किसी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया गया था। एसएनएचआर के अध्यक्ष फदेल अब्दुल गनी के अनुसार देश में अनेक स्थानों पर सामूहिक कब्रें मिली हैं, जिनमें पुराने शासक ने लोगों को कत्ल करने के बाद दफन कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब तक एक दर्जन से ज्यादा सामूहिक कब्रों का पता लगाया जा चुका है और इस तरह की अन्य कब्रों की तलाश जारी है। अब्दुल गनी ने कहा कि इन कब्रों से जो अवशेष बरामद होंगे उनका डीएनए टेस्ट कराने के बाद उन्हें संबंधित व्यक्ति के परिवारजनों के हवाले कर दिया जाएगा।

रोजनामा सहारा (31 दिसंबर) के अनुसार सीरिया के सैन्य संचालन विभाग ने जनता से अपील की है कि वे सामूहिक कब्रों को तहस-नहस न करें। ऐसा करने से उनमें दफनाए गए व्यक्तियों की पहचान नहीं हो सकेगी। विभाग ने देशवासियों से अपील की है कि अगर उन्हें ऐसी कब्रों की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत इसके बारे में सरकार को सूचित करें। सरकार ने सीरियाई जनता से अपील की है कि पुराने शासन ने जिनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार करने के बाद लापता कर दिया था उनसे जुड़े सभी दस्तावेजों को वे सरकार के हवाले कर दें। सीरियन सिविल डिफेंस (एससीडी) के निदेशक राएद अल सालेह ने कहा कि विशेष जांच टीमें सामूहिक कब्रों की जांच कर रही हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास डीएनए टेस्ट से संबंधित उपकरणों की कमी है, इसलिए इन कब्रों से अब तक जो अवशेष मिले हैं उनकी जांच में कठिनाई आ रही है।

उर्दू टाइम्स (23 दिसंबर) के अनुसार बशर अल-असद के शासनकाल में सीरियाई जेलों के प्रमुख रहे जमील हसन देश से फरार हो गए हैं। जब सरकारी सेना उनके आवास में दाखिल हुई तो उनके टेबल पर आधा खाया हुआ खाना पड़ा हुआ था। इससे प्रतीत होता है कि बशर अल-असद के देश से फरार होने की खबर मिलने के बाद वे आनन-फानन में सीरिया से भाग गए थे। उन्हें बशर अल-असद के शासनकाल में 'कसाई' के नाम से याद किया जाता था। सरकार विरोधी लाखों लोगों की हत्या के पीछे जमील हसन का हाथ बताया जाता है। वे सीरियाई वायुसेना की खुफिया एजेंसी के प्रमुख थे। उनकी गिनती बशर अल-असद के विश्वस्त लोगों में की जाती थी। अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख डॉलर के ईनाम की घोषणा कर रखी है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने किस देश में शरण ली है।

हिंदुस्तान (27 दिसंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि 1971 से सीरिया की सत्ता पर काबिज असद परिवार के तख्ता पलट के बाद उनके घिनौने कारनामों का पर्दाफाश हो रहा है। सीरिया की भूमि का चप्पा-चप्पा लाशें उगल रहा है। अब तक दो दर्जन से अधिक सामूहिक कब्रिस्तानों का पता लगाया जा चुका है। इन कब्रिस्तानों के सुरक्षाकर्मी बताते हैं कि हर दिन देश के विभिन्न स्थानों से 400 लाशें कंटेनरों में भरकर लाई जाती थीं, जिनसे आवारा कुत्ते अपना पेट भरते थे। इसके बाद उन लाशों को 20-20 मीटर गहरे कब्रों में दफना दिया जाता था। गुप्त दस्तावेजों के अनुसार सिर्फ दमिश्क में ही 150 सामूहिक कब्रों का पता चला है। इन दस्तावेजों के अनुसार सीरियाई वायुसेना की खुफिया एजेंसी के सैनिक एक बार में 200-300 लोगों को ट्रकों में भरकर लाते थे और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। इसके बाद उनके शवों को पेट्रोल डालकर जला दिया जाता था। शवों के जो अवशेष बचते थे उन्हें इन कब्रों में दफना दिया जाता था।

सरकारी दस्तावेजों के अनुसार सीरिया की असद सरकार द्वारा 2011 से लेकर अब तक 10 लाख लोगों की हत्या की जा चुकी है। जबकि

एक करोड़ 30 लाख लोग बेघर हो गए हैं। असद सरकार अपने विरोधियों की लाशों से छुटकारा पाने के लिए भिन्न-भिन्न तरीके अपनाती थी। इनमें लाशों को जलाना भी शामिल था। इन लाशों को जलाने के लिए बिजली से चलने वाली बड़ी-बड़ी भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था। जेलों में बंद मासूम लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें दशकों तक अंधेरे कमरों में बंद रखा जाता था। सीरिया की कार्यवाहक सरकार ने जेलों से जिन लोगों को रिहा किया है उनमें से सैकड़ों कैदी पागल हो चुके हैं।

सीरिया द्वारा ईरान से 300 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग

इंकलाब (27 दिसंबर) के अनुसार सीरिया की कार्यवाहक सरकार ने गृहयुद्ध के दौरान देश में हुई क्षति की पूर्ति के लिए ईरान से 300 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग की है। इस संदर्भ में ईरान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि पिछले 13 सालों के गृहयुद्ध के दौरान ईरान सरकार सीरिया की बशर अल-असद सरकार का सैन्य समर्थन करती रही है। इसके कारण सीरिया की अर्थव्यवस्था और जनता को भारी क्षति उठानी पड़ी और देश का पूरा अर्थ तंत्र तबाह हो गया। अगर ईरान सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता तो यह नौबत नहीं आती। ईरान ने इस गृहयुद्ध के दौरान बशर अल-असद के समर्थन में अरबों डॉलर खर्च किए। इसके अतिरिक्त ईरानी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) के हजारों सैनिकों को बशर अल-असद सरकार का समर्थन करने के लिए सीरिया भेजा गया ताकि वे सत्ता में बरकरार रह सके। ईरान की इस नीति के कारण सीरिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

सीरिया के कार्यवाहक विदेश मंत्री असद अल-शिबानी ने ईरान सरकार को चेतावनी दी है कि वह सीरिया के मामले में हस्तक्षेप न करे। ईरान को सीरियाई जनता की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ईरान और उसके सहयोगियों को सीरिया में अशांति फैलाने की अनुमति नहीं देंगे। हाल ही में एक बार फिर से सीरिया में विद्रोह फूट पड़ा है और इसके पीछे भी ईरान का ही हाथ है। ईरान यह नहीं चाहता कि सीरिया की जनता अपने भाग्य का निर्णय अपनी इच्छा से करे। वह सीरिया को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। हम इसका विरोध करते हैं। ईरान को हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जो तत्व ईरान के इशारे पर देश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें सख्ती से कुचल दिया जाएगा।

मिस्र में फिलिस्तीनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध

कौमी तंजीम (29 दिसंबर) के अनुसार मिस्र सरकार ने सीरिया और चार अन्य अरब देशों से आने वाले फिलिस्तीनियों के मिस्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी सूत्रों ने अल अरेबिया को बताया कि मिस्र सरकार ने सीरिया, सूडान, लीबिया, इराक और यमन से आने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों के मिस्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले मिस्र सरकार ने यूरोप अमेरिका और कनाडा में रहने वाले सीरियाई नागरिकों के मिस्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस फैसले का उद्देश्य अमेरिकी वीजा रखने वाले सीरियाई नागरिकों को मिस्र में प्रवेश करने से रोकना है। इसके अतिरिक्त विदेशों में रहने वाले मिस्री मूल के लोगों के भी देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मिस्र के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम सीरिया की वर्तमान सरकार का समर्थन करते हैं और सीरिया के नवनिर्माण में पूरा सहयोग देंगे।

इजरायल द्वारा यमन पर भीषण बमबारी

उर्दू टाइम्स (20 दिसंबर) के अनुसार इजरायल ने यमन की राजधानी साना में तेल के भंडारों और बिजली घरों पर हमले किए हैं। साना हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। इन हमलों के कारण हूतियों के तीन बंदरगाह तबाह हो गए हैं। दक्षिणी साना का सबसे बड़ा बिजली घर भी इजरायली हमले में तबाह हो गया है। कहा जाता है कि इन हमलों में 200 हूती विद्रोही मारे गए हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि हूतियों के खिलाफ ये सैन्य कार्रवाई इसलिए की गई है, क्योंकि वे इजरायल को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। हालांकि, इजरायल हूतियों द्वारा दागे गए अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर देता है। हमास ने यमन पर इजरायली हमले की निंदा की है और धमकी दी है कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमले हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते हैं।

कौमी तंजीम (20 दिसंबर) के अनुसार इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने यह घोषणा की है कि हम इजरायल की ओर उठने वाला हर

हाथ काट देंगे। हूतियों को यह जान लेना चाहिए कि हमारे लंबे हाथ उन तक पहुंच चुके हैं। जो भी इजरायल को नुकसान पहुंचाएगा उसे सात गुना ज्यादा जवाब दिया जाएगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि ईरान सरकार हूतियों को आर्थिक सहायता के अतिरिक्त हथियार और गुप्त सूचनाएं उपलब्ध करा चुकी है। हम इजरायल के किसी भी विरोधी को सहन नहीं करेंगे और ईरान के इशारे पर नाचने वाली सभी कठपुतलियों का सफाया कर देंगे।

मुंसिफ (20 दिसंबर) के अनुसार इजरायली सेना ने यमन में हूतियों के ठिकानों, बंदरगाहों, तेल के भंडारों और बिजली घरों पर हमलों का सिलसिला जारी रखा है। इन हमलों में साना के दो बिजली घरों और तेल के अनेक भंडारों को तबाह कर दिया गया है। इजरायल द्वारा ये हमले हूतियों के इजरायल पर हमले के जवाब में किए गए हैं। हूतियों ने यह घोषणा की है कि वे इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं। इजरायल पर हमारे मिसाइल हमले लगातार जारी रहेंगे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (24 दिसंबर) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना हमास और हिजबुल्लाह को बर्बाद कर चुकी है। अब हमारा अगला निशाना हूती हैं। इजरायल के अतिरिक्त अमेरिकी सेना ने भी हूतियों को अपना निशाना बनाया है। अमेरिका ने ये हमले उनके जहाजों पर हूतियों द्वारा किए गए हमले के जवाब में किए हैं।

हिंदुस्तान (26 दिसंबर) के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने मध्य इजरायल पर एक दर्जन से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इन हमलों के कारण इजरायल के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। हूतियों ने यह दावा किया है कि वे इजरायल पर हमलों का सिलसिला जारी रखेंगे।

एतेमाद (24 दिसंबर) के अनुसार ईरान ने अमेरिका द्वारा यमन पर किए जाने वाले हमलों को अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने दावा किया है कि ये हमले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और उसके सिद्धांतों के खिलाफ हैं। बाघेई ने मुस्लिम जगत और संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि वे यमन पर अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल द्वारा किए जा रहे हमले को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करें। एक अन्य समाचार के अनुसार हूती विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-18 को तबाह कर दिया है।

औरंगाबाद टाइम्स (25 दिसंबर) के अनुसार इजरायल ने यूरोप में अपने राजनयिक मिशनों को निर्देश दिया है कि वे हूती विद्रोही समूह को एक आतंकवादी संगठन घोषित करवाने के लिए संबंधित देशों की सरकारों से संपर्क स्थापित करें और यह जोर दें कि हूती सिर्फ इजरायल के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। उनके हमलों से लाल सागर में जहाजों की व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई हैं।

तुर्किये की एक फैक्ट्री में विस्फोट

अवधनामा (25 दिसंबर) के अनुसार तुर्किये के गृह मंत्री अली येर्लिकाया ने घोषणा की है कि उत्तर-पश्चिमी तुर्किये में विस्फोटक पदार्थ बनाने वाली एक फैक्ट्री में हुए धमाके में 12 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं। धमाके के कारण फैक्ट्री की पूरी इमारत तबाह हो गई है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने इस धमाके पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने इस धमाके की उच्चस्तरीय जांच कराने का आदेश दिया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यह एक आतंकवादी हमला है। गौरतलब है कि पिछले कई दशक से तुर्किये में अनेक आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। इनमें आईएसआईएस, अलकायदा और पीकेके आदि प्रमुख हैं।

उल्लेखनीय है कि आतंकवादियों ने 23 अक्टूबर 2024 को तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुख्यालय पर हमला किया था। इस हमले में 20 लोग मारे गए थे। मरने वालों में पांच आतंकवादी भी शामिल थे। इससे पहले इस्तांबुल ट्रेड सेंटर में भी एक विस्फोट हुआ था। इसकी जिम्मेवारी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने ली थी। इस हमले में 15 लोग मारे गए थे, जिनमें एक आत्मघाती हमलावर भी शामिल था। तुर्किये की वायुसेना तुर्किये और इराक की सीमा पर स्थिति आईएसआईएस के ठिकानों को लगातार अपना निशाना बना रही है। तुर्किये खुफिया विभाग ने दावा किया है कि पिछले साल तुर्किये में 2700 इस्लामिक आतंकवादी पकड़े गए थे, जिनमें कई महिलाएं और इजरायली एजेंट भी शामिल थे।

RNI No. DELHIN/2017/72722

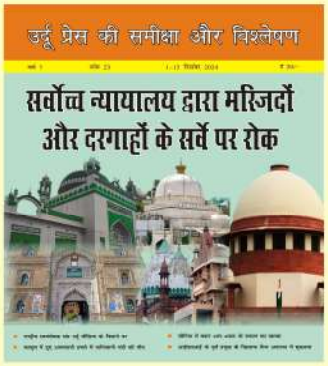

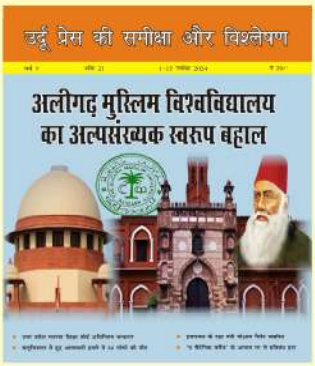

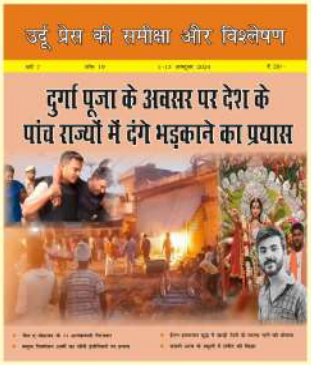

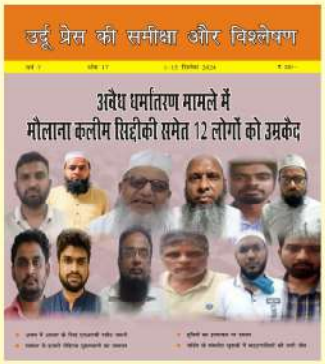

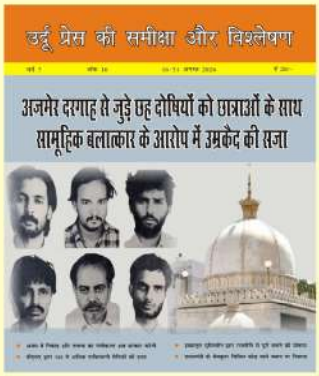

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in